*बारिश और तेज हवा से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। गुरूवार को चली तेज हवा और बारिश से खेतों में खड़ी फसलें आड़ी गिर गई तथा कई जगहों कटी फसलों को बचाने के लिए किसानों को जूझते हुए देखा गया। यह तस्वीर 14 नम्बर चंदवाजी बाईपास के पास की है, जहां गेहूं की फसल आड़ी गिर गई है।*
***फोटो-दिनेश भारद्वाज***

# तमिलनाडु में भी राज्यपाल और प्रदेश सरकार के बीच खींचतान की शुरुआत हुई

## राज्यपाल आर.एन. रवि ने ऑनलाइन गेमिंग/जुए पर प्रतिबंध लगाने को लेकर विधानसभा से पारित विधेयक को वापस लौटा दिया

चेन्नई, 9 मार्च (वार्ता)। तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने को लेकर विधानसभा से पारित विधेयक को वापस लौटा दिया है।

विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने लगभग 140 दिनों तक रखने के बाद इस विधेयक को वापस लौटाने को लेकर रवि की निंदा की है। तमिलनाडु में ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन खेलों के नियमन विधेयक को 19 अक्टूबर, 2022 को विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। सरकार ने यह कदम राज्य में ऑनलाइन जुआ में लाखों रुपये के नुकसान के कारण लोगों की आत्महत्या की घटनाओं के मद्देनजर उठाया था। मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. चंद्रू के नेतृत्व वाली एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों के बाद 1 अक्टूबर, 2022 को राज्य सरकार एक अध्यादेश के जरिए विधेयक लेकर आई थी। अगस्त 2021 में मद्रास उच्च न्यायालय ने पिछले अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम सरकार द्वारा अधिनियमित तमिलनाडु गेमिंग और पुलिस कानून (संशोधन) अधिनियम को रद्द कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने समिति का गठन किया था।

विधेयक को राजभवन द्वारा इस विधेयक को यह कहते हुए वापस किया गया है कि विधेयक को अधिनियमित करने के लिए राज्य विधानमंडल के पास "विधायी क्षमता नहीं है"।

राज्यपाल ने अपनी स्थिति को पुख्ता करने के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मसौदा संशोधन सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दायित्व और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 का उल्लेख किया, जिसके लिए जनवरी में सार्वजनिक प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई थी। गत वर्ष अक्टूबर में राज्य विधानसभा में स्वीकृत विधेयक को राज्यपाल के पास उनकी सहमति के लिए भेजा गया था। राज्यपाल ने पिछले साल नवंबर में राज्य के कानूनी मामलों के विभाग को पत्र लिखकर ऑनलाइन जुआ पर प्रतिबंध लगाने और ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए विधेयक की कुछ धाराओं पर स्पष्टीकरण मांगा था। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी पहले रवि से मुलाकात की थी और उनसे राज्य विधानसभा द्वारा पारित लंबित विधेयकों को मंजूरी प्रदान करने की अपील की थी। उन्होंने विधेयक को मंजूरी प्रदान करने में राज्यपाल की ओर से अत्यधिक देरी किए जाने पर नाराजगी भी व्यक्त की थी। उन्होंने जानना चाहा था कि राज्यपाल को इसके लिए अपनी सहमति देने के लिए कितनी मौतों की आवश्यकता है। इस बीच मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कषगम (एम.डी.एम.के.) महासचिव एवं राज्यसभा सांसद वाइको और पट्टाली मक्कल काची (पी.एम.के.) अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद डॉ. अंबुमणि रामदास सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने विधेयक को लगभग 140 दिनों तक रखने के बाद वापस लौटाने के लिए राज्यपाल की कड़ी निंदा की है।

उन्होंने डीएमके सरकार से 20 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में एक बार फिर इस विधेयक को पारित करने का आग्रह किया और कहा कि राज्यपाल को निश्चित रूप से इस पर अपनी सहमति देनी चाहिए। वाइको ने कहा कि ऑनलाइन जुआ के कारण 47 लोगों ने आत्महत्या की है और राज्यपाल को इन मौतों की जिम्मेदारी लेनी होगी। उन्होंने विधेयक को 142 दिनों तक रोककर वापस करने के लिए राज्यपाल की कड़ी निंदा भी की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस संबंध में राज्य विधानसभा में एक और विधेयक लाना चाहिए और संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल को इसके लिए अपनी सहमति देनी चाहिए। वाइको ने कहा कि राज्यपाल संविधान के अनुसार कार्य करने के बजाय सनातन बलों के प्रचार प्रचारक के रूप में कार्य कर रहे थे।

## जब तक एडवोकेट प्रोटैक्शन...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

शर्मा, एडवोकेट बार एसोसिएशन जोधपुर के अध्यक्ष रणजीत जोशी, लॉयर्स बार एसोसिएशन जोधपुर के अध्यक्ष रवि भंसाली, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के महासचिव बलराम वशिष्ठ व दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष विवेक शर्मा व महासचिव गजराज सिंह राजावत ने हिस्सा लिया। मंत्री धारीवाल कोटा से वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के जरिए जुड़े। उन्होंने वकीलों से कहा कि प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की राज्य सरकार की मंशा पहले भी थी और अब भी है। राज्य सरकार ने 2021 में भी बीसीआर को बिल भेजकर सुझाव मांगे थे। उन्होंने वकीलों से कहा कि चाहें तो वे दो दिन में अपने सुझाव दे दें। जिस पर बार प्रतिनिधियों ने कहा कि बीसीआर बिल पर विचार कर उसे पहले ही राज्य सरकार को लौटा चुका है। ऐसे में राज्य सरकार मौजूदा प्रोटेक्शन बिल को ही पारित कर एक्ट को लागू कर दे। दोनों पक्षों की सहमति से बिल को 15 मार्च को विधानसभा में पेश करने और 21 को पारित करने का निर्णय लिया गया। दरअसल बीसीआर के तत्कालीन चेयरमैन चिरंजीलाल सैनी ने 22 जनवरी, 2020 को राज्य सरकार को पत्र भेजकर उसके सौ दिन की कार्य योजना में शामिल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की बात कही थी। गत 18 फरवरी को जोधपुर में वकील की हत्या के बाद वकीलों ने प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हुए बीस फरवरी से न्यायिक बहिष्कार शुरू किया था। संघर्ष समिति की बैठक में होगा निर्णय- अधिवक्ता संघर्ष समिति के मुख्य संयोजक कमल किशोर शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार व वकीलों के बीच हुई बैठक में हुए निर्णय को शुक्रवार को संघर्ष समिति की बैठक में रखा जाएगा। उसमें ही न्यायिक कार्य बहिष्कार को स्थगित या वापस लेने और 13 को विधानसभा घेराव पर निर्णय लिया जाएगा।

## 'अडानी मामले में ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

उन्होंने मोदी से कहा कि वे झूठ पकड़ने वाला टैस्ट (लाइ डिटेक्टर टैस्ट) दें। उन्होंने पूछा, "प्रधानमंत्री स्वयं पर तथा अडानी पर लगाये गये आरोपों के विषय में कुछ भी क्यों नहीं बोलते? क्या उनमें देश के सामने आने का साहस है?" के.टी.आर. जो बी.एस.आर. के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ने कहा, "यह एक राजनैतिक प्रतिशोध है। मोदी आग से खेल रहे हैं तथा उन्हें जल्दी ही इसका अहसास हो जायेगा।"

प्रधानमंत्री मोदी को "पाखण्ड का परदादा" कहते हुये, के.टी.आर. ने कहा कि "डराने-धमकाने की नीति" तेलंगाना में कारगर नहीं होगी। ज्ञातव्य है कि तेलंगाना में विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं। उनकी बहिन तथा बी.आर.एस. नेता के. कविता को जारी हुये "ई.डी. के सम्मनों" को "मोदी के सम्मन" कहते हुये, के.टी.आर. ने कहा कि पिछले चन्द महीनों में, विपक्षी नेताओं को डराने-धमकाने के लिये, ई.डी., आई.टी. तथा सी.बी.आई. ने 11 बी.आर.एस. नेताओं के यहाँ छापे मारे थे। उन्होंने आगे कहा, "अगर वे (भाजपा) राजनैतिक कारणों से विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान करने की कोशिश करेंगे, तो बी.आर.एस. उनसे जनता की अदालत में लड़ेगी।"

# मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्र.मंत्री एंथनी अल्बनीज़ के साथ पूरे क्रिकेट स्टेडियम का चक्कर लगाया

## दोनों नेताओं ने साथ चलते हुये बेहद गर्मजोशी से अहमदाबाद में दोनों देशों की जनता का बहुत जोर-शोर से अभिवादन भी किया

नई दिल्ली, 9 मार्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टैस्ट मैच से पहले डिप्लोमेसी की ऐसी पारी खेली कि इससे चीन को मिर्ची लग गई होगी। वैसे भी पी.एम. इशारों इशारों में संदेश देने में माहिर हैं। यही कारण है कि पी.एम. मोदी ने क्वाड के सदस्य देश ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाया और यह बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिक रिश्तों में क्रिकेट की कितनी अहमियत है। खेल के मैदान से खेल खेल में पी.एम. मोदी ने ऑस्ट्रेलिया से दोस्ती की ऐसी इबारत रची कि क्रिकेट से अनजान देश चीन को मिर्ची लग गई होगी। क्योंकि चीन क्वाड के सदस्य देशों के मिलने पर हमेशा से ही आपत्ति जताता है। उसे लगता है कि भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ये चार देश जब भी मिलते हैं, चीन के खिलाफ ही साजिश रचते हैं।

हालांकि भारत में क्वाड की हालिया बैठक में चीन को यही संदेश दे दिया गया है कि वह कायदे में रहे, तो फायदे में रहेगा। चीन चुपचाप अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन करता रहे, यही नसीहत दी गई। अब ऑस्ट्रेलिया के पी.एम. भारत दौरे पर हैं, दोनों क्रिकेट के मैदान पर साथ जिस गर्मजोशी से भारतीय जनता का अभिवादन कर रहे हैं, यह तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि क्वाड के देशों में शामिल ये दो देश भारत और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती कितनी प्रगाढ़ है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा और आखिरी टैस्ट शुरू होने से पहले अहमदाबाद स्टेडियम पहुंचकर भी प्रधानमंत्री ने बड़ा संदेश दिया। वो गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ पहुंचे। भले ही दोनों प्रधानमंत्री क्रिकेट मैदान में थे, लेकिन संदेश खेल की सीमा से इतर कूटनीति के मैदान तक पहुंच गया। निश्चित रूप से क्रिकेट के मैदान पर क्वाड देशों के दो प्रधानमंत्रियों की एकजुटता के प्रदर्शन वाली तस्वीर से कूटनीति के मैदान में बड़ी चाल चली गई है।

समुद्र में चीन की बढ़ती चुनौतियों के मद्देनजर क्वाड देश नई-नई रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। चारों देश विकास से लेकर सामरिक मुद्दों पर एक-दूसरे की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में भारत ने साल 2020 में पहली बार अपने बहुचर्चित नौसैनिक अभ्यास मालाबार में ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया। अब इस वर्ष अगस्त महीने में पहली बार मालाबार नौसैनिक अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। भारत मालाबार एक्सरसाइज में अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों के साथ-साथ लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान भी भेजेगा।

चीन के साथ बिगड़े रिश्तों के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती साझेदारी को काफी अहम माना जा रहा है। चीन काफी तेजी से अपनी नौसेना का विस्तार कर रहा है। वह पहले से ही 355 युद्धपोतों और पनडुब्बियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। क्वाड देशों को इसका मतलब अच्छे से पता है, इसलिए आने वाले वर्षों में किसी भी चुनौती से निपटने के लिए समुद्री साझेदारी की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

क्वाड के सभी चार सदस्यों ने चीन की आपत्तियों को दरकिनार कर दिया और साफ कहा है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में किसी उसकी प्रकार की जबरदस्ती नहीं चलने दी जाएगी। चीन को भी क्वाड के इतर भारत-ऑस्ट्रेलिया के निजी संबंधों की भी अच्छे से खबर है। भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर एक साल में तीन बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चा चुके हैं। पिछले साल उन्होंने क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मेलबर्न का दौरा किया था। हालिया दौरे में उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के लिए विश्व की दिशा तय करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है।

## खड़गे ने क्यों ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

का क्या, उनके बारे में पार्टी की सोच क्या है?

सूत्रों का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्णयों में गांधी परिवार द्वारा दखलंदाजी किए जाने की न तो संभावना है और न ही वह इसका इच्छुक है। एक नेता ने इस पर टिप्पणी की कि, "अगर सोनिया और राहुल गांधी में गहलोत को बदलने की हिम्मत होती तो वे अब तक या फिर खड़गे के अध्यक्ष बनने से पहले ही यह कर चुके होते।

संदेश साफ है, राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के वायदे तो कई बार किए पर राहुल ने कभी भी इस वायदे पर अमल नहीं किया।

कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है कि "9.3 करोड़ जनता इंदिरा रसोई योजना" थालियों द्वारा जनता को पौस्टिक आहार प्रदान किया है।

हमारा प्रण-

"कोई भूखा न सोए"

इसलिए जन-जन को मिले केवल 8 रू. में भोजन।।

कांग्रेस सरकार-जन सरोकार

# बाघिन टी-134 को सरिस्का भेजा

सवाई माधोपुर, 9 मार्च (निसं)। रणथम्भौर बाघ परियोजना सवाई माधोपुर की रेंज खण्डार से मादा बाघ टी-134 को सरिस्का बाघ परियोजना में शिफ्ट किया गया।

उप वन संरक्षक मोहित गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण व मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर के आदेशों की पालना में एसओपी की पालना करते हुए टी-134 बाघिन को ट्रेंकुलाइज कर पकड़ा तथा आवश्यक जांच कर स्वस्थ अवस्था में सरिस्का टीम को सौंपा गया। बाघिन टी-134 को दोपहर 1.40 बजे सरिस्का के लिए रवाना किया गया। यह बाघिन लगभग 3 वर्ष 6 माह की है जो अब तक अपनी टेरेटरी यहां स्थापित नहीं कर पाई थी। टी-134 बाघिन की मां टी-93 है जो अब नए शावकों के साथ विचरण कर रही है। इस क्षेत्र में अन्य बाघों का विचरण रहता है।

बाघिन का ट्रांसलोकेशन ऑपरेशन मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव एवं क्षेत्र निदेशक रणथम्भौर बाघ परियोजना एस.आर. यादव के नेतृत्व में किया गया।

ट्रांसलोकेशन ऑपरेशन में क्षेत्र निदेशक सरिस्का आर.एन. मीणा, उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक कैलादेवी करौली डॉ. आर.एन. भाकर, उप वन संरक्षक उप क्षेत्र निदेशक प्रथम रणथम्भौर बाघ परियोजना मोहित गुप्ता, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक प्रतिनिधि संजीव शर्मा, उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना बूंदी, डीपी जागावत उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक सरिस्का, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के प्रतिनिधि अभिषेक भटनागर, अरूण शर्मा सहायक वन संरक्षक, विष्णु गुप्ता रेंजर, डॉ. सीपी मीणा, डॉ. राजीव गर्ग, डॉ. डी.डी. मीणा एवं रेस्क्यू प्रभारी राजवीर सिंह व अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

**■ रणथम्भौर बाघ परियोजना सवाई माधोपुर की खंडार रेंज की इस बाघिन को ट्रैंकुलाइज कर सफलतापूर्वक ट्रांसलोकेट किया गया।**

## 'इंसाफ विपक्षी दलों का कॉमन...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

से रहे असहिष्णुता के स्तर के खिलाफ है। पिछले शनिवार को नया संगठन बना चुके सिब्बल प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनाम नागरिकों की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि इंसाफ विपक्षी पार्टियों के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर सकता है और इन पार्टियों के नेता वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों से पूर्व एकजुट हो सकते हैं। उन्होंने विपक्षी एकता और लोकसभा चुनावों से पूर्व इसका क्या स्वरूप हो सकता है, को लेकर बात की। तथापि, उन्होंने कहा कि वह इंसाफ के माध्यम से विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सहमति जताई कि विभिन्न पार्टियां एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के रूप में उनके प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि "सभी पार्टियों को एकजुट करने वाला मैं कौन होता हूं? मैंने हाल ही में कहा है कि पार्टियों को यह प्लेटफॉर्म जॉइन करना चाहिए। विपक्ष की प्रत्येक पार्टी किसी ना किसी तरीके से अन्याय का लक्ष्य बनती आई है। अत: यह एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म हो सकता है, जिसके जरिए हम सभी आगे बढ़ सकते हैं। अन्तत: जनता को हमें यह स्पष्ट करना है कि हम किस चीज़ के खिलाफ हैं और यह अन्यायी सरकार धीरे-धीरे हर उस चीज को नष्ट कर रही है, जिसके सहारे यह संविधान खड़ा है। यह प्लेटफॉर्म राजनीतिक है।"

## मोबाइल फोन क्यों तोड़े...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

मोबाइलों फोनों की कथित रूप से नष्ट कर दिये जाने के बारे में पूछताछ की गई। इस समय वे न्यायिक हिरासत में हैं। सी.बी.आई. ने उन्हें 2021-22 की दिल्ली शराब एवं एक्साइज पॉलिसी को लागू करने में कथित भ्रष्टाचार जुड़ाव के सिलसिले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उनसे जेल में पूछताछ करने के लिये, ई.डी. ने स्थानीय अदालत ने अनुमति ले ली है।

अदालत में पेश की गई चार्ज शीट में इसने सिसोदिया पर विभिन्न आरोप लगाये हैं। उन पर आरोप लगाया गया है कि दिल्ली सरकार की 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी में शराब व्यापारियों को लाइसैंस दिए गए ताकि वे "कार्टेलाइजेशन" कर सकें। इस प्रकार उन डीलर्स को फायदा पहुंचाया गया, जिन्होंने इसके लिय कथित रूप से रिश्वत दी थी।

आप पार्टी ने इस आरोप का सख्ती से खण्डन किया है। बाद में, यह नीति रद्द कर दी गई तथा दिल्ली एल.जी. ने इसकी सब.बी.आई. जाँच की अनुशंसा कर दी। इसके फलस्वरूप, ई.डी. ने आरोपी के खिलाफ प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट (पी.एम. एल.ए.) के तहत केस दर्ज कर दिया।

*बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक का गुरुवार तड़के दिल का दौरा पड़ने से गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया, वे 67 वर्ष के थे। अभिनेता सतीश कौशिक का पोस्टमार्टम भी कराया गया तथा शाम को उनके शव पर अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में अभिनेता एवं निर्देशक कौशिक की मौत का कारण हार्ट अटैक ही बताया गया है। अनुपम खेर ने सतीश कौशिक के निधन की जानकारी देते हुए ट्वीट किया, जानता हूँ मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है! सतीश कौशिक ने वर्ष 1983 में रिलीज फिल्म 'जाने भी दो यारों' से अभिनय की शुरुआत की थी। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। कौशिक को अभिनय में मिस्टर इंडिया फिल्म कैलेंडर के किरदार से पहचान मिली। उन्होंने हास्य के साथ-साथ गंभीर किरदार भी निभाये। उन्हें वर्ष 1990 में फिल्म 'राम लखन' और वर्ष 1997 में फिल्म 'साजन चले ससुराल' के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित किया था।*

# मुसलमानों को लुभाने के लिए भाजपा...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

मुस्लिम समाज के नेता ही राज्य के अतिक्रमण-विरोधी अभियान का निशाना बने थे। "शमसान-कब्रिस्तान" बहस तथा टीपू सुल्तान तथा औरंगज़ेब जैसे मुस्लिम शासकों के उल्लेख प्राय: भाजपा नेताओं के चुनावी भाषणों का केन्द्रीय विषय रहे हैं। इस सबके बावजूद, अगर भाजपा, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, साम्प्रदायिक समरसता की दिशा में पहल करने की कोशिश कर रही है, तो इसके कुछ तर्कसंगत एवं ठोस कारण हैं। खासतौर से राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में, मुस्लिमों और हिन्दुओं के बीच परम्परागत एवं सांस्कृतिक जुड़ाव है तथा दोनों ही समुदाय के लोगों के "सरनेम" भी प्राय: एक जैसे (कॉमन) हैं। दोनों ही समुदायों के लोगों के नामों के साथ त्यागी, चौहान, तौमर तथा राव जैसे सरनेम देखे जा सकते हैं। जहाँ 2013 में मुजफ्फर नगर में हाल ही इतिहास का एक बहुत ही बुरा साम्प्रदायिक दंगा हुआ था, इसके बावजूद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द के माहौल की शुरुआत करने का माद्दा है। पिछले चुनावों में, संगीत सोम जैसे स्थानीय भाजपा नेता मुस्लिमों को निशाना बनाते हुये उत्तेजनक बयान देते हुये अक्सर सुनाई देते थे, जो साफ तौर पर मतदाताओं को धार्मिक आधार पर ध्रुवीकृत करने की कोशिश थी। भाजपा रणनीतिकार 2024 के पहले अपनी उन रणनीतियों को छोड़ देने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं।

यह मानते हुये कि अल्पसंख्यक-विरोध भाजपा को यहीं तक ले जा सकता है, इससे आगे नहीं, पार्टी रणनीतिकार दोहरे उद्देश्यों वाली रणनीति पर काम कर रहे हैं- एक तरफ तो, अपने कट्टर हिन्दू मतदाताओं को संतुष्ट करने के लिये पार्टी के अल्पसंख्यक-विरोध पर डटे रहना और इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय तक पहुँचकर अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश करना। अभी हाल ही में, पार्टी ने पसमन्दा मुस्लिमों (दलित-मुस्लिमों) का एक सम्मेलन आयोजित किया था तथा उन्हें केन्द्र और राज्य सरकार की विभिनन योजनाओं के लाभों की जानकारी दी थी। पार्टी एक "सूफी सम्वाद महा अभियान" संचालित करने की भी योजना बना रही है, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही होगी। भाजपा के "उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी फ्रन्ट के अध्यक्ष कुँवर बासित अली ने कहा, "ऐसी भी संभावना है कि इस प्रकार के कार्यक्रम राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों तक भी पहुँचा दिये जायें।"

# 'मोदी के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान द्वारा की गई ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

इन दोनों परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों के बीच एक हिंसक चक्र चलने का जोखिम है। भारत और पाकिस्तान ने वर्ष 2021 की शुरुआत में लाइन ऑफ कंट्रोल (एल.ओ.सी.) पर युद्ध विराम पुन: लागू किया था। अब नई दिल्ली और इस्लामाबाद वर्तमान की इस शांति को शायद आगे जारी रखना चाहेंगे।

"हालांकि, भारत-विरोधी उग्रवादी गुटों को समर्थन देने का पाकिस्तान का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व के अधीन पाकिस्तान के किसी वास्तविक या अनुभूत उकसावों के प्रति भारत के पहले की तुलना में सैन्य प्रतिक्रिया देने की संभावना अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रत्येक पक्ष यह मानकर चल रहा है कि कश्मीर में हिंसक अशांति या भारत के किसी स्थल पर किसी संभावित उग्रवादी हमले से तीव्र होने वाला कोई भी तनाव सैन्य संघर्ष का जोखिम बढ़ा सकता है। सीमा पार आतंकवाद और कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान के संबंध तनावपूर्ण रहते आए हैं। भारत का मानना है कि आतंकवाद और वार्ता, दोनों एक साथ नहीं चल सकते तथा इस्लामाबाद को बातचीत पुन: शुरु करने के लिए एक सकारात्मक वातावरण तैयार करना चाहिए।

इस बीच, पाकिस्तान और अमेरिका आतंकवाद रोधी मुद्दे को लेकर एक दौर की बातचीत पूर्ण कर चुके हैं। इन दो-दिवसीय वार्ताओं में कई मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग, आतंक रोधी क्षेत्रीय भू-भाग का आकलन, सायबर सिक्योरिटी और हिंसक चरमपंथ सहित कई विषय शामिल थे। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने आतंकवाद के लिए होने वाली फंडिंग को रोकने के लिए अपने-अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने सभी तरह के आतंकवाद की एक समान चुनौती का समाधान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी।

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नैड प्राइस ने कहा कि अमेरिका-पाकिस्तान के बीच हुई आतंकवाद रोधी बातचीत उग्रवादी चुनौतियों और हिंसक चरमपंथ का मुकाबला करने में अमेरिका को पाकिस्तान के साथ काम करने का अवसर प्रदान करती है। प्राइस ने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा की चुनौतियों से निबटने में हमारा साझा हित है।

उन्होंने कहा कि "आतंकवाद मुक्त क स्थिर एवं सुरक्षित दक्षिण व मध्य एशिया का लक्ष्य पाकिस्तान के साथ हमारी साझेदारी की मजबूती पर निर्भर है।" उन्होंने कहा कि यह बातचीत सुरक्षा के एक स्वस्थ संबंध और क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्थायित्व को चुनौती देने वाले सभी आतंकवादी गुटों का मुकाबला करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर स्पष्ट वार्ता का अवसर उपलब्ध करवाती है और हमारी साझा प्रतिबद्धताओं का एक इच्छापत्र है। वह एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे, जिसमें उनसे पूछा गया था कि कश्मीर में सक्रिय लश्कर ए तैय्यबा तथा खालिस्तानी उग्रवादी गुटों जैसे आतंकवादी गुटों को पाकिस्तान की सेना और आई.एस.आई. के समर्थन का मुद्दा क्या अमेरिका ने इस्लामाबाद के साथ उठाया है। प्राइस ने कहा कि "इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए अमेरिका अपनी साझेदारी को विस्तृत करना चाहता है। कोई भी समूह, जो क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्थायित्व को चुनौती पेश करता है, वह हमारे लिए चिन्ता का विषय है। आतंकवाद रोधी बातचीत में हमने ऐसी ही कुछ बातों पर चर्चा की।"

## गैर कम्युनिस्ट नेता रामचंद्र पौडेल नेपाल के नये राष्ट्रपति बने

काठमांडू, 9 मार्च। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल गुरुवार को नेपाल के नये राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। राष्ट्रपति चुनाव में आज हुए मतदान में 78 वर्षीय पौडेल ने अपने प्रतिद्वंद्वी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सुभाष नेम्वांग को दोगुने से अधिक अंतर से पराजित किया।

निवर्तमान राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी का कार्यकाल 12 मार्च को समाप्त हो रहा है। नेपाल के चुनाव आयोग के अनुसार कुल 52 हजार 628 मतों में से पौडेल को 33 हजार 802 मत तथा नेम्वांग को 15 हजार 518 वोट हासिल हुए।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908